

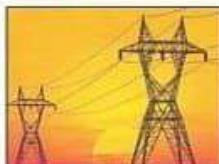
बिजली आपूर्ति में यूपी ने किया टॉप

महाराष्ट्र को पीछे छोड़ा, 28704 मेगावाट मांग के सापेक्ष 28284 की आपूर्ति कर बनाया रिकॉर्ड

अमर उजला व्युगे

लखनऊ। उपभोक्ताओं को पीक आवस्य में बिजली देने के मामले में यूपी देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। ओबरा को 660 मेगावाट की एक नई यूनिट का ट्रायल पूरा हो गया है। वहां से उत्पादन भी शुरू हो गया है। 660 मेगावाट की जबाहरपुर की एक अन्य यूनिट जनवरी में शुरू होगी। ओबरा व जबाहरपुर में 660-660 मेगावाट की एक-एक यूनिट निर्माणाधीन भी है। इन्हें भी मई से पहले चलाने की तैयारी है।

अपनी तक बिजली आपूर्ति में महाराष्ट्र नंबर एक पर था। राज्यसभा में 19 दिसंबर को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर तक पीक आवस्य में यूपी ने यह रिकॉर्ड तोड़ा है। यूपी में मांग 28704 मेगावाट थी, जिसके सापेक्ष 24 जुलाई को अधिकतम 28284 मेगावाट की आपूर्ति की गई। वही, महाराष्ट्र 31178 के सापेक्ष 27996 मेगावाट की ही आपूर्ति कर पाया। अब नए सौजन के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने मांग का लक्ष्य 30 हजार मेगावाट से अधिक का बनाया है। इसके तहत



30,000 मेगावाट से अधिक का लक्ष्य

■ पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आशोप कुमार गोपल ने बताया कि पीक सौजन के लिए 30 हजार मेगावाट से अधिक की मांग होने की उम्मीद को देखते हुए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। उत्पादन बढ़ाने के साथ ही बैंकिंग से भी इंतजाम किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को समस्या न हो।

तैयारी शुरू हो गई है। इसी क्रम में ओबरा की नई यूनिट से उत्पादन शुरू हुआ है। इसको 765 केवी के अनपरा डी से उन्नाव पारेशन लाइन से जोड़कर परीक्षण किया गया है। अब इसे ग्रिड से जोड़कर 72 घंटे पूरी क्षमता से चलाया जाएगा। जबाहरपुर की 660 मेगावाट की एक यूनिट का ट्रायल चल रहा है। इसे जनवरी के पहले सप्ताह में चलाने की तैयारी है। उपभोक्ता परिषद ने इस उपलब्धि पर सरकार को बधाई दी है।

डिजिटल लेनदेन में भी रिकॉर्ड वृद्धि

लखनऊ (अधिकारी गुप्ता)। डिजिटल लेनदेन में यूपी में जबर्दस्त वृद्धि हुई है। केवल एक साल में यह करीब तीन गुना बढ़ गई है। पांच साल की बात करें तो यूपी बालों ने छह गुना रफतार से डिजिटल बैंकिंग को अपनाया है। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेनदेन में यूपी देश में चौथे स्थान पर है।

एक साल में तीन गुनी बढ़तीरी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के मुताबिक पिछले वर्ष 426.68 करोड़ डिजिटल लेनदेन यूपी में हुए। इस साल ये संख्या बढ़कर 1174.32 करोड़ हो गई। एक साल की ये तेजी कोरोना काल से भी ज्यादा है। इसकी बजाह डिजिटल बैंकिंग की आसान पहुंच, गांवों तक इंटरनेट, वित्तीय जागरूकता और लेनदेन उपकरणों की पर्याप्त संख्या है। समिति के मुताबिक काल के बाद कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने आधार और रुपे कार्ड आधारित जमा व भुगतान पर विशेष जोर दिया। ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी जिलों में बैंकों ने मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, भीम एप, इंटरनेट बैंकिंग और डेविट कार्ड को लेकर अधिकान ढेरा है।

■ डिजिटल रूप से पिछड़े आठ जिले बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र के लिए खास अधिकान चलाया गया। नवीजा निकल कि फतेहपुर, चित्रकूट और सोनभद्र ने लक्ष्य से औसतन दोगुनी ज्यादा सफलता प्राप्त की।

>> डिजिटल के साथ-साथ नकदी लेनदेन भी बढ़ा : पेज 4